

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 22.12.2024
समय 07.20

मुख्य समाचार :-

- राज्य के आठ जिलों में सौ दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अब तक तेईस हजार आठ सौ तपेदिक रोगियों को निःक्षय मित्रों ने गोद लिया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा— राज्य का समग्र विकास सरकार का लक्ष्य।
- वस्तु और सेवा कर परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की।
- प्रयागराज महाकुंभ-2025 में उत्तराखंड का अपना पवेलियन होगा।

टी.बी. उन्मूलन अभियान बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में 100 दिवसीय टी.बी. उन्मूलन अभियान के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के आठ जिलों में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 23 हजार 800 टीबी मरीजों को निःक्षय मित्रों द्वारा गोद लिया गया है। इसके साथ ही, टीबी के खिलाफ जारी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मोबाइल एक्स-रे मशीनों और निःक्षय वाहनों की तैनाती की गई है।

मुख्यमंत्री संबोधन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य का समग्र विकास सरकार का लक्ष्य है। देहरादून में एक समाचार चैनल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि पहाड़ की महिलाओं का जीवन आसान बनाने और राज्य में पलायन की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने आगामी राष्ट्रीय खेलों और समान नागरिक संहिता के लागू होने का जिक्र करते हुए कहा कि ये कदम राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सिलक्यारा सुरंग निर्माण

उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य इन दिनों पूरी गति से जारी है। इस सुरंग का महत्व केवल उत्तरकाशी से बड़कोट तक के सफर को आसान बनाने में ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास और यातायात को नई दिशा देने में भी है। उत्तरकाशी से हमारे जिला संवाददाता के अनुसार, इस सुरंग का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल तक यह सुरंग पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

वर्तमान में, सुरंग निर्माण का कार्य कर रही कंपनी का कहना है कि अगर कोई अप्रत्याशित बाधा नहीं आती, तो यह सुरंग अप्रैल माह तक आर-पार हो जाएगी। इस परियोजना के तहत एक तीसरी ड्रिफ्ट टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूस्खलन के मलबे को सुरंग से बाहर निकालना है। यह टनल 15 फरवरी तक तैयार होने की संभावना है। वहीं, दो ड्रिफ्ट टनल पहले से तैयार हो चुकी हैं, जिनकी मदद से सुरंग के अंदर डिवाटरिंग का काम चल रहा है। तीसरी ड्रिफ्ट टनल का निर्माण अभी भी जारी है, जिसमें कुल 55 मीटर का काम बाकी है, और अब तक 5 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है।

पिछले साल नवम्बर में भूस्खलन के कारण सुरंग निर्माण कार्य में व्यवधान आया था। उस समय इस सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन चले बचाव अभियान के बाद सकुशल बाहर निकाला गया था। इस घटना के बाद से सिलक्यारा छोर पर भूस्खलन का मलबा सुरंग निर्माण में प्रमुख बाधा बना हुआ है। हालांकि, सुरंग के दूसरे छोर पोलगांव (बड़कोट) की ओर खोदाई का कार्य लगातार जारी है। अब सिर्फ 175 मीटर सुरंग की खुदाई बाकी रह गई है, और हर दिन लगभग डेढ़ मीटर की खुदाई की जा रही है। इस परियोजना का सफलतापूर्वक पूरा होना न केवल स्थानीय जनता के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगा, बल्कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय विकास में भी एक नई गति प्रदान करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में यह सुरंग उत्तरकाशी और बड़कोट के बीच यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुगम बना देगी।

आकाशवाणी देहरादून के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मानव डोभाल।

निर्देश

दिल्ली में वाहनों की प्रवेश में आ रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली मार्ग पर बसों की सेवाएं सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सीएनजी और बीएस-6 मॉडल की बसों को दिल्ली मार्ग पर चलाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम का उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी परेशानी के दिल्ली यात्रा में मदद करना है।

अविरल प्रवाह कार्यक्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में आयोजित गंगधारा-विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संस्कृति और समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन और समान नागरिक संहिता पर भी प्रकाश डाला।

जीएसटी बैठक संपन्न

राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े कई फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और पहले से पैकेट बंद तथा लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीन-थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है। साथ ही बैंकों और एनबीएफसी के दंड शुल्क, देर से भुगतान शुल्क पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के प्रशिक्षण भागीदारों को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है, लेकिन यह फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा।

कार्यशाला

टिहरी वन प्रभाग के पौखाल और भिलंगना रेंज में वन विभाग के फ़ील्ड कर्मचारियों का एक दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण और वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान

कर्मचारियों को विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। पौखाल की उप प्रभागीय वनाधिकारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि विभाग सभी रेंज में इस तरह की कार्यशाला करेगा जिससे वन विभाग के कर्मचारियों को फील्ड पर काम करने में परेशानी नहीं होगी।

प्रयागराज कुंभ—उत्तराखंड पवेलियन भूमि आवंटन

प्रयागराज महाकुंभ—2025 में उत्तराखंड का अपना पवेलियन होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उत्तराखंड को सेक्टर-7 कैलाशपुरी मार्ग, पूर्वी पटरी प्रयागराज में 100×400 वर्ग फिट भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी है। इस भूमि पर उत्तराखंड का पंडाल सजेगा, जहां मेलार्थियों को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पवेलियन में सुविधाओं का प्रबंध करेगी और मेलार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर—

केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में जारी की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023...इस खबर को सभी अखबार पत्रों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है देश में वन आवरण बढ़ा, उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में घटा। इसी समाचार पर नवोदय टाइम्स का शीर्षक है— दो वर्ष में देश में बढ़ा 1445 वर्ग किमी वन क्षेत्र, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देहरादून में आंकड़े किए सार्वजनिक।

दो दिवसीय यात्रा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे हैं....इस खबर को प्रमुखता देते हुए नवोदय टाइम्स लिखता है— भारतीय ने कुवैत के कैनवास में भरे कौशल के रंग। हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रधानमंत्री के संबोधन को ही सुर्खी बनाकर लिखता है— संघर्षों का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता।

जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक की खबर को भी सभी अखबार पत्रों ने प्रमुखता दी है। सहारा लिखता है जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले, बीमा प्रीमियम पर नहीं हो सका कोई निर्णय, जीन थैरेपी व एटीएफ जीएसटी से बाहर। अमर उजाला का शीर्षक है— पुराना वाहन खरीदना होगा

महंगा, 12 के बजाय 18 प्रतिशत लगेगा जीएसटी। वहीं, दैनिक जागरण लिखता है पुरानी ईवी और छोटी कार खरीदना होगा महंगा।

देश में चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है। इस खबर को सभी अखबारों ने मुख्य रूप से जगह से दी है। दैनिक जागरण का शीर्षक है— आम लोग नहीं देख सकेंगे चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। नवोदय टाइम्स लिखता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का नहीं हो सकेगा सार्वजनिक निरीक्षण। वहीं, राष्ट्रीय सहारा की खबर है— नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण।